30. All tenancies, hereinafter created, should be exempted from rent control.

NSDP in Gujarat

2466. SHRI AHMED PATEL: Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Planning Commission is implementing and monitoring the National Slum Development Programme (NSDP) in the State of Gujarat;

(b) if so, the details thereof;

(c) in how many slums of the State, provisions of adequate water supply, sanitation and primary eduction facilities were provided under NSDP during the last two years, year-wise;

(d) whether the desired effects of the programme were noticed in the slums so covered under NSDP in the State; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI RAM JETHMALANI): (a) and (b) Under the scheme of National Slum Development Programme (NSDP) funds are being allocated by the Planning Commission and releases are made by the Department of Expenditure, Ministry of Finance. The Ministry of Urban Affairs & Employment has been nominated as the Nodal Ministry to monitor the scheme at Central level.

(c) The Government of Gujarat has informed that projects covering 141 slum areas of 5 Municipal Corporation and 9 Nagarpalikas have been sanctioned to provide various facilities/services as laid down in the scheme.

(d) and (c) Since the scheme is at an initial stage of implementation in the State of Gujarat, it is difficult to assess the effect of the programme in the slums covered under NSDP.

लक्ष्मीबाई नगर में सरकारी मकानों का उचित रख-रखाव

2467. **श्रीमती मालती शर्मा:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि के०लो०नि०वि० के "घ" मंडल के अंतर्गत आने वाले लक्ष्मीबाई नगर के श्रेणी-II मकानों के उचित रख-रखाव के कार्य की विद्युत तथा सिविल कर्मचारी उपेक्षा कर रहे हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या कर्मचारियों को इस बात की जानकारी है कि भू-तल के मकानों का स्तर सड़क के स्तर की तुलना में नीचे चला गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार संबंधित कर्मचारियों को जिनकी उपेक्षा के कारण इन मकानों में सीलन हुई है, मकानों का तथा उनके बाहरी मुख्य द्वार की सीमा का स्तर उठाने के लिए उचित अनुदेश देगी?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां। के०लो०नि०वि० को इस बात की जानकारी है कि कुछ भू-तल के मकानों का फर्श का स्तर सड़क के स्तर की तुलना में नीचा है।

(ग) भू-तल के कुछ मकानों सीलन की समस्या तब होती है जब बरसाती पाइपों से बारिश का पानी सही तरह से नहीं निकल पाता है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद से क्षेत्र की जल निकासी में सुधार के लिए उपयुक्त कदम उठाने के लिए अनुरोध किया गया है। मकानों का स्तर और बाहरी मुख्य द्वार की सीमा का स्तर उठाना आवश्यक समझा नहीं गया है।

डी० आई० जेड० क्षेत्र, नई दिल्ली में झोपड़ पट्टियां

2468. **श्री मुनव्वर हसन:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई दिल्ली के डी०आई०जेड० क्षेत्र में स्थित झोपड़ पट्टियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विभिन्न क्षेत्रों में बनी झोंपड़ पट्टियों को हटाने के लिए सरकार द्वारा अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या काली-बाड़ी मार्ग स्थित दूर-संचार विभाग की भूमि को खाली कराने के लिए दूर-संचार विभाग द्वारा स्लम संबंध के पास 4.5 करोड़ रुपये जमा करवाये गये थे;

(घ) यदि हां, तो स्लम स्कंध ने दूर-संचार विभाग की भूमि को अब तक खाली क्यों नहीं करवाया; और

(ङ) सरकार दूर-संचार विभाग की भूमि से झुग्गियां कब तक हटा देगी?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) एन डी एम सी ने सूचित किया है कि डी आई जेड एरिया में आज झुग्गी-झोपड़ी समूह है।

(ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि दिल्ली के विभिन्न भागों से 65 झुग्गी-झोपड़ी समूह हटाए गए हैं।

(ग) दूर संचार किया ने 1481 पात्र झुग्गी निवासियों को क्षेत्र से हटाने के लिए पुर्नस्थापना लागत के अंश के रूप में दिल्ली नगर निगम को लगभग 4.29 करोड़ रूपय का भुगतान किया है।

(घ) ज्यादातर पात्र झुग्गी निवासियों को दिल्ली नगर निगम द्वारा पुर्नस्थापित कर दिए जाने की सूचना मिली है। शेष पात्र और अपात्र झुग्गी निवासियों के संबंध में दूर संचार विभाग ने मामला दिल्ली नगर निगम के साथ उठाया है।

JJ Cluster on DDA Plot

2469. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether on a DDA plot of land in a posh locality in South Delhi surrounded by Mandakini Enclave, Kalka Public School, Aravali Apartment, a JJ cluster has become a nuisance creating law and order problem;

(b) whether Government had stated earlier on the floor of the House in reply to a question that the said plot which was earmarked for housing a community centre, would be got vacated from JJ cluster; and

(c) if so, by when the work for construction of community centre would be completed especially in the light when double storey pakka structures are coming up in the cluster?

THE MINISTER OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYEMENT (SHRI RAM JETHAMALANI): (a) Delhi Police has reported that there is a jhuggi cluster on DDA land opposite Mandakini Enclave known as Alaknanda camp about which two complaints were received. These complaints were passed on the DDA for necessary action.

(b) and (c) DDA has reported that Slum Department of the MCD has desired to conduct a fresh joint survey to sort out the number of eligible/non-eligible jhuggi dwellers. The construciton work of the Community Centre can be taken up only after clearance of the JJ cluster.

Infrastructure Development in Mega Cities

2470. SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMET be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the centrally sponsored schemes for infrastructural development in mega cities was launched;

(b) if so, when was it launched and what are the objectives;

(c) the projects taken up so far; and

(d) the details of the achievements?

THE MINISTER OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI RAM JETHMALANI): (a) Yes, Sir,

(b) The Centrally Sponsored Scheme for development of infrastructure in five mega cities of Mumbai, Calcutta, Chennai, Hyderabad and Bangalore was initiated during 1993-94. The objective of the scheme is to create and maintain a Fund for the development of infrastructural assets on a continuing basis.